

running to the extent possible with the help of management staff/ Home guards/casual workers.

(ii) Despatches of LPG from Bombay were stepped up.

Distribution of Gas from Bombay High

1784. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV;
SHRIMATI SURYAKANTA
JAYAWANTRA PATIL:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the State-wise distribution of Bombay High gas;

(b) what is the estimated yearly requirement of gas of the Government of Maharashtra; and

(c) the quantum of gas sanctioned to the State of Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER AND MINISTERS OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) Natural gas is being supplied, subject to availability, to individual consumers and not to the States. At present, only one consumer (Kribhco Fertilizer Plant at Hazira in Gujarat) outside Maharashtra is being supplied natural gas from Bombay High.

(b) The Government of Maharashtra have requested supply of associated gas from Bombay High to the city of Bombay to meet its domestic, industrial and commercial requirements assessed by them at about 2.20 million cubic metres per day.

(c) At present, about 8 million cubic metres per day of associated gas is being brought from Bombay High to the Uran Terminal, where processing facilities are limited to

this quantity; after meeting the internal requirements and LPG extraction, the entire remaining quantity of gas to the tune of about 6.8 to 6A million cubic metres per day is being supplied to various industrial consumers in Maharashtra.

Oil Production from Oil Well at Narimanam at Tanjavur

1785. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) how much oil is being produced since the commissioning of the oil well at Narimanam at Tanjavur in Tamil Nadu;

(b) how far the drilling at Thevur has progressed since the beginning of drilling operation on March 20, through Russian made 3DM rig;

(c) whether ONGC will begin drilling in the Pak bay for oil; and

(d) if so, what method will be adopted for the purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER AND MINISTERS OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) About 14 tonnes per day.

(b) 3503 metres till 1st August, 1986.

(c) Yes, Sir.

(d) It is proposed to drill wells in Pak Bay by charter hired shallow jack-up rig.

कोयला खदान का घंटना

1786. श्री शरद यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13-14 अक्टूबर, 1986 की रात को मध्य प्रदेश के बड़दोल जिले में स्थित लोयसारा गांव में कोयले की एक खदान जमीन में घंसे

गई थी जिससे हजारों श्रमिकों की जानें खतरे में पड़ गई थीं ; यदि हाँ, तो इस संग्रह में क्या कहा है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार खान-सुआ विभाग के अधिकारियों और खान प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) दिनांक 13-14 जुलाई, 1986 की रात में भारी वर्षा के कारण बिजुरीह खान के लोहसरा इन्क्लाइन में विकसित कार्यस्थलों पर छिछले कवर एरिया में 25X15 मीटर का पाट-होल बन गया था। वर्षा का पानी पाट-होल के जरिए भूमिगत क्षेत्र में घुसने लगा परन्तु कोई मीत नहीं हुई क्योंकि प्रभावित क्षेत्र के नोचे या उसके आसपास कोई कामगार काम पर नहीं लगाया गया था। दिनांक 14 जुलाई, 1986 की प्रातः सत्र पर एक बांध बनाया गया ताकि वर्षा का पानी पाट-होल की ओर नहीं जाकर दूसरी ओर जाए। जो पानी भूमिगत खान में एकत्र हो गया था, उसे भाँप से बाहर निकाल दिया गया। चूंकि यह दुर्घटना कुछ ही घंटों में 76 मि.मी. तक असामान्य भारी वर्षा होने से हुई और यह ऐसी घटना थी जिस पर प्रबंधमंडल का नियंत्रण नहीं था, इसलिए कर्तव्य की उपेक्षा के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

उन किसानों के परिवारों के सदस्यों को रोजगार, जिनकी भूमि का कोयला-खनन कार्य हेतु अधिग्रहण किया गया है

1787. श्री शरद यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी करके यह निर्देश दिया है कि उन किसानों के परिवार के किसी भी सदस्य को रोजगार न दिया जाए जिनकी तीन एकड़ से कम भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश आदिवासी किसानों के पास तीन एकड़ से भी कम भूमि है, और यदि हाँ, तो क्या सरकार परिपत्र में संशोधन करने का विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं। कोयला विभाग की यह नीति है कि यदि संबद्ध परियोजना में रोजगार की गुंजाइशें हों तो नौकरी देने में भू-विस्थापितों को वरीयता दी जाए। सरकार ने आदेश जारी करके सरकारी उपक्रमों द्वारा अधिग्रहीत भूमि के मालिकों को, उनसे अधिग्रहीत भूमि के आकार का विचार किए बिना रोजगार देने की पुरानी कार्य प्रथा बिल्कुल सामप्त कर दी है। फिर भी ऐसी प्रत्येक परियोजना में—जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है—भूवंचितों के लिए पुनर्वास के अन्य उपाय किए जाएंगे।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आदिवासी किसानों के स्वामित्व वाली भूमि के एकड़ों की संख्या का कोई महत्व नहीं है।

Conference of Power Ministers

1788. SHRI K. VASUDEVA PANICKER; Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a conference of Power Ministers of States was held in Delhi on 14th July, 1986 to discuss augmentation of power generation and supply in different States; and

(b) if BO, what are the details of the discussions held and the outcome thereof?